the said steep increase in the procurement and minimum support prices of paddy and other kharif crops including groundnut and whether it would not result in the increase in prices of other essential commodities; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to check the price rise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI UPENDRA NATH VERMA): (a) The procurement / minimum support prices for Rabi crops of 1989-90 to be marketed in 1990-91 season were revised in April, 1990.

(b) All commodities Wholesale Price Index (base 1981-82 = 100) for March, 1990, i.e. before the revision of procurement / minimum support prices for Rabi crops was 170.1. After the announcement of the prices for Kharif crops of 1990-91, the Wholesale Price Index in July, 1990 (average for 3 weeks) was 178.1.

The price movements of essential commodities etc. depend on factors like production, supply and demand situation, money supply, general price situation, international prices etc.

(c) Steps being taken by Government include judicious release of essential commodities through the Public Distribution System, augmented availability through enhanced production and / or imports if necessary, stringent measures to prevent hoarding and black marketing, fiscal and monetary measures, etc.

राजकीय सहायता से कृषि उपकरण उपलब्ध कराये जाने की योजना

694. **श्री बलराम सिंह यादव:**
श्रीमती कैलाशपति:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसानों को राजकीय सहायता से कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बनाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना कब लागू की जायेगी और किसानों को कृषि उपकरण प्रदान किये जाने की पात्रता के संबंध में क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा खाद्य तेलों के मूल्यों पर नियंत्रण

695. **श्री बलराम सिंह यादव:**
श्रीमती कैलाशपति:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के आंतरिक बाजारों में खाद्य तेलों की कीमतों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को सौंपी थी;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड ने इस समय खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(ग) इन उपायों से प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार): (क) सरकार, खाद्य तेलों के मूल्यों का नियंत्रण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्य तेलों को निर्मुक्त करके और मण्डी हस्तक्षेप कार्य के द्वारा करती है। भारत सरकार ने खाद्य तेलों / तिलहनों में मण्डी हस्तक्षेप कार्य को कार्यान्वित करने के लिए सरकार की समेकित तिलहन नीति के तहत पत्र संख्या 25030 / 2 / 88- व्यापार के द्वारा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को मण्डी हस्तक्षेप एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। मण्डी हस्तक्षेप कार्य का उद्देश्य तिलहनों और तेलों को इस प्रकार खरीदना व बेचना है कि मूंगफली और सरसों के तेल के थोक